श्रीमान आयुक्त, आयकर विभाग, कलकत्ता

बनाम

गिलेंडर्स आर्बुथनॉट एंड कंपनी.

विपरीतता से

27 सितम्बर, 1972

(के.एस. हेगड़े,, पी. जगनमोहन रेड्डी,, आई.डी. दुआ

और एच.आर. खन्ना, जे.जे.)

आयकर अधिनियम 1922 की धारा 12बी और 34-पूंजीगत लाभ-लेन-देन चाहे बिक्री हो, पुनर्समायोजन हो या विनिमय-आयकर अधिकारी लेन-देन द्वारा बनाए गए कानूनी संबंध के अलावा लेन-देन के सार पर जा सकते हैं या नहीं-शेयर-पूर्ण मूल्य -जहां बिक्री मूल्य है, उसे पूर्ण मूल्य माना जाना चाहिए-मूल्यांकन को फिर से खोलना धारा 24(1)(ए) के तहत नोटिस की वैधता।

निर्धारिती, एक पंजीकृत फर्म है जो ज्यादातर एजेंसी व्यवसाय का प्रबंधन करती है एवं मूल रूप से इसमें चार भागीदार शामिल थे। दिनांक 28 फरवरी, 1947 को साझेदारी विलेख द्वारा, एक सीमित कंपनी (जिसके

एकमात्र शेयरधारक निर्धारिती फर्म के चार भागीदार थे) को पांचवें भागीदार के रूप में लिया गया था। कंपनी को रुपये की राशि के बदले नवगठित फर्म में 99% की हिस्सेदारी दी गई थी। इसे मौजूदा साझेदारों को 14,90,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, 28 फरवरी, 1947 को' '

रुपये की राशि 75,00,000/- रूपये, अक्षरे पिचहत्तर लाख रूपये में कंपनी को हस्तांतरित कर दी। उपरोक्त रकम रु. 14,90,000 और 75 लाख रु. कंपनी द्वारा मौजूदा साझेदारों को अंकित मूल्य पर अपने शेयर आवंटित करने से वह संतुष्ट हुए। निर्धारण वर्ष 1947-48 के संबंध में आयकर अधिकारी ने किसी भी पूंजीगत लाभ को ध्यान में रखे बिना मूल रूप से मूल्यांकन किया। बाद में उन्होंने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 के तहत नोटिस जारी किया और यह मानते हुए एक नया मूल्यांकन किया कि निर्धारिती फर्म ने रुपये के लिए अपनी शेयरधारिता की बिक्री पर, अन्य बातों के साथ, 75 लाख रूपये पूंजीगत लाभ कमाया था। क्योंकि, कंपनी द्वारा निर्धारिती फर्म को दिए गए शेयरों का बाजार मूल्य रुपये 75 लाख रूपये अंकित मूल्य से बहुत अधिक था। धारा 34 के तहत नोटिस की वैधता को अधिकारियो के साथ-साथ न्यायालय के संदर्भ में भी बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि विचाराधीन लेनदेन धारा 12 बी के प्रावधानों को आकर्षित करने वाली एक 'बिक्री थी और पूंजीगत लाभ

रूपये 27,4,772/- रूपये था। इस आधार पर कि निर्धारिती फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य रुपये 75 लाख था। राजस्व के साथ-साथ निर्धारिती फर्म द्वारा दायर की गई अपीलों में जो प्रश्न विचाराधीन थे वे थे; (1) क्या धारा 34 (1)(ए) के तहत नोटिस मामले की परिस्थितियों में वैध रूप से जारी किया गया था; (2) क्या विचाराधीन लेन-देन 'बिक्री था जैसा कि यह बिक्री के समझौते के तहत होना चाहिए या निर्धारिती फर्म द्वारा दावा किया गया एक मात्र पुनः समायोजन था, या राजस्व द्वारा दावा किया गया विनिमय था; (3) क्या पूंजीगत लाभ की गणना निर्धारिती फर्म को आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य के आधार पर की जानी थी या उनके मूल्य के आधार पर की जानी थी जैसा कि 'बिक्री के समझौते में दिखाया गया है जो कि 75 लाख रूपये।

अभिनिर्धारित किया गया:

(१) हालांकि मूल मूल्यांकन के समय, पांच भागीदारों द्वारा दर्ज की गई साझेदारी विलेख आयकर अधिकारी के समक्ष थी, बिक्री विलेख निर्धारिती फर्म के भागीदारों द्वारा कंपनी के पक्ष में दिनांक 28 फरवरी, 1947 को निष्पादित किया गया को उनके सामने नहीं रखी गई थी। आयकर अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह यह निष्कर्ष निकाल सके कि निर्धारिती फर्म ने 'कंपनी को कोई शेयर

और प्रतिभूतियां बेची थीं; न ही आयकर अधिकारी के समक्ष उन शेयरों और प्रतिभूतियों के मूल्य के बारे में कोई सामग्री थी।

1 जनवरी, 1939 इसके अलावा उनके सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई कि वे शेयर और प्रतिभूतियाँ 'कंपनी को 75 लाख रुपये की राशि में बेची गई थीं। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने सही माना कि निर्धारिती पूरी तरह से खुलासा करने में विफल रहा है। वास्तव में सभी भौतिक तथ्य यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं कि इससे कोई पूंजीगत लाभ हुआ है या नहीं। (445 बी.)

कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, कंपनी जिला-1, कलकत्ता एवं अन्य, 41 आई.टी.आर. 191, में समझाया और लागू किया गया।

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और अन्य। वी. हेमचंद्र कर और अन्य, 77 आई.टी.आर. पी 1, आयकर आयुक्त गुजरात बनाम भानजी लवजी, 79 आई.टी.आर. 583 और आयकर आयुक्त कलकत्ता बनाम बर्लोन डीलर्स लिमिटेड, 79 आई.टी.आर. 609, संदर्भित।

(२) धारा 12-बी को 1 अप्रैल 1947 से अधिनियम में शामिल किया गया था। ऐसा होने पर, जिस समय बिक्री लेनदेन हुआ था। 12-बी अधिनियम का हिस्सा नहीं था। इसलिए यह कहने का कोई आधार नहीं था

कि स्थानांतरण करदाता के दायित्व को टालने या कम करने के उद्देश्य से किया गया था। (447 डी)

(३) कर लगाने वाला प्राधिकारी लेनदेन के परिणामस्वरूप वास्तविक कानूनी संबंध निर्धारित करने का हकदार है और वास्तव में बाध्य है। यदि पार्टियों ने किसी युक्ति द्वारा कानूनी संबंध को छुपाने का विकल्प चुना है, तो कर लगाने वाले प्राधिकारी के पास इस युक्ति को उजागर करने और संबंध के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन किसी लेन-देन के कानूनी प्रभाव को 'लेनदेने के सार' की जांच करके विस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों पर समान रूप से लागू होता है जिनमें कानूनी संबंध औपचारिक दस्तावेज़ में दर्ज किया जाता है और ऐसे मामलों में जहां इसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और लेन-देन के पक्षों के आचरण से इकट्ठा किया जाना होता है। (449 बी)

आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम बी.एम. खरवार, 72 आई.टी.आर. 603 ने अनुसरण किया।

सर कीकाभाई प्रेमचंद बनाम आयकर आयुक्त (केंद्रीय)। बम्बई, 24, आई.टी.आर. 506, आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी बनाम सर होमी मेहता के निष्पादक, 28 आई.टी.आर. 928, रोजर्स एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-11, 344, आई.टी.आर. 336 और आयकर आयुक्त

(केंद्रीय) कलकत्ता बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी। 47. आई.टी.आर. 565, संदर्भित।

मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनल ने माना था कि निर्धारिती फर्म और 'कंपनी' के बीच किया गया बिक्री समझौता वास्तविक, लेनदेन था और यह बिक्री का सबूत है। यह मूलतः तथ्य की खोज थी और उच्च न्यायालय ने उस खोज की पुष्टि की थी। उस दृष्टि से राजस्व का तर्क है कि प्रश्न में लेन-देन एक विनिमय था, न कि बिक्री और निर्धारिती का तर्क था कि यह केवल समायोजन था। स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सी.एल. समझौते के (1) में विशिष्ट शर्तों में कहा गया है कि "मौजूदा साझेदार बेचेंगे और कंपनी पचहत्तर लाख रुपये की राशि के लिए शेयर और प्रतिभूतियां खरीदेगी। उस समझौते के खंड (3) ने केवल एक तरीका प्रदान किया है बिक्री मूल्य की संतुष्टि। बेचे गए शेयरों और प्रतिभूतियों के लिए पार्टियों द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य 75 लाख था और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है कि बिक्री मूल्य की संतुष्टि में कंपनी के शेयरों के आवंटन के कारण, निर्धारिती फर्म को कुछ लाभ मिले लेकिन इसने बिक्री को विनिमय में परिवर्तित नहीं किया। (449 ई)

आयकर आयुक्त, केरल बनाम बी.आर. रामकृष्ण पिल्लई, 66. आई.टी.आर. 725 और आयकर आयुक्त. पश्चिम बंगाल और और. बनाम जॉर्ज हेंडरसन एंड कंपनी लिमिटेड 59 आई.टी.आर. 238, संदर्भित।

उपरोक्त कारणों से यह माना जाना चाहिए कि कंपनी और निर्धारिती के बीच बिक्री के समझौते से प्रमाणित लेनदेन बिक्री था।

(४) धारा 12-बी(2) के तहत पूंजीगत लाभ की राशि की गणना उस प्रतिफल के 'पूर्ण मूल्य से कुछ कटौती करने के बाद की जानी चाहिए जिसके लिए बिक्री की गई है। किसी कीमत पर बिक्री के मामले में, विनिमय के मामले के विपरीत किसी भी बाजार मूल्य का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में जिनमें धारा 12-बी की उप-धाराओं (2) का पहला प्रावधान है, जो कि आकर्षित नहीं है, केवल देखने के लिए सौदेबाजी की गई है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर पहला प्रावधान लागू नहीं किया गया था। शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए प्राप्त मूल्य सीमा केवल पचहत्तर लाख रुपये थी। उच्च न्यायालय ने सही माना कि पूंजीगत लाभ रु. 2,74,772 है (450 सी)

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम जॉर्ज हेंडर सन एंड कंपनी लिमिटेड, 66 आई.टी.आर. 622, अनुसरण किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1452 और 1502/1969

उच्च न्यायालय, कलकत्ता के 1966 के आयकर संदर्भ संख्या 101 में 13 सितंबर, 1968 के निर्णय और आदेश से प्रमाण पत्र द्वारा अपील।

एस. सी. मनचंदा, बी. बी. आहूजा, एस. पी. नायर और आर. एन. सच- वे, अपीलकर्ताओं के लिए (सी. ए. नंबर 1452/69 में और प्रतिवादी के लिए (सी. ए. नंबर 1502/69 में)।

डी. पाल, टी. ए. रामचन्द्रन और डी. एन. गुप्ता, उत्तर के लिए- डेंट (सी.ए. नं. 1452/69 में) और अपीलकर्ता (सी. ए. नं. में 1502/69).

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

केएस हेगड़े, जे.

ये प्रमाणपत्र द्वारा क्रॉस-अपील हैं। वे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (आगे इसे अधिनियम के रूप में संबोधित किया जाएगा) की धारा 66 (1) के तहत एक संदर्भ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए हैं। निर्धारिती के साथ-साथ आयुक्त के कहने पर, आयकर न्यायाधिकरण की 'बी' बेंच कलकत्ता ने एक मामले की सुनवाई की और उसकी राय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय को पांच प्रश्न प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में कुछ प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पारित नहीं किए गए हैं। इसलिए हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे हमारे सामने जो प्रश्न रखे गए थे वे हैं:

(1) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही वैध रूप से शुरू की गई है?

2) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, धारा 12-बी के अर्थ के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ को कंपनी के प्रवेश के लिए निर्धारिती द्वारा रखे गए निवेश के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन से उत्पन्न होने के लिए कहा जा सकता है। निर्धारिती फर्म में भागीदार के रूप में और जनता को कंपनी के शेयर जारी करना; और

(3) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण को रुपये पर पूंजीगत लाभ की गणना करना कानूनन उचित था। 46,76,784/-?

उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और राजस्व के पक्ष में दिया। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, इसे दो प्रश्नों में विभाजित किया गया है। क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, धारा 12-बी के अर्थ के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ को निर्धारिती द्वारा कंपनी में रखे गए निवेश के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन से उत्पन्न होने के लिए कहा जा सकता है और क्या तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, धारा 12-बी के अर्थ के भीतर किसी भी पूंजीगत लाभ को निर्धारिती फर्म में भागीदार के रूप में कंपनी के प्रवेश और जनता के लिए कंपनी के शेयरों को जारी करने से उत्पन्न होने वाला कहा जा सकता है? इसने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक और राजस्व के पक्ष में और दूसरे भाग का नकारात्मक और राजस्व के विरुद्ध उत्तर दिया। जहां तक तीसरे प्रश्न का

संबंध है, उच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, पूंजीगत लाभ की गणना रुपये में की जानी चाहिए थी। 27,04,772/-. इस निर्णय से व्यथित होकर आयकर आयुक्त ने 1969 की सिविल अपील संख्या 1452 और निर्धारिती ने 1969 की सिविल अपील संख्या 1502 लायी है।

निर्धारिती की अपील में आग्रह किया गया एकमात्र तर्क यह था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही वैध रूप से शुरू नहीं की गई है और इस मामले के तथ्यों के अनुसार धारा 12-बी है आकर्षित नहीं. आयुक्त द्वारा अपील में, निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि पूंजीगत लाभ के रूप में धारा 12-बी के तहत कर के दायरे में लाई जाने वाली सही राशि क्या है। राजस्व के वकील ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का विरोध नहीं किया कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, धारा 12-बी के अर्थ के तहत कोई भी पूंजीगत लाभ कंपनी की स्वीकृति से उत्पन्न नहीं हुआ होगा। निर्धारिती कंपनी का भागीदार और जनता को कंपनी के शेयर जारी करना। इसलिए इन मामलों में हमें बस इतना तय करना है कि (1) क्या धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही वैध है,(2) क्या 12 B केस के तथ्यों को समझा पा रहा है, और (3) यदि 12B समझा पाता है तो पूंजीगत लाभ कितना बनेगा?ऊपर दिए गए प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए भौतिक तथ्यों का उल्लेख करना

आवश्यक है। निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म है जो ज्यादातर कंपनियों के प्रबंध एजेंटों के रूप में कारोबार कर रही थी। फरवरी 1947 के अंत तक, फर्म में चार साझेदार शामिल थे, अर्थात् (1) एसी ग्लैडस्टोन; (2) एसडी ग्लैडस्टोन; (3) टीएस ग्लैडस्टोन और (4) ग्लेनडाई लिमिटेड, उनमें से प्रत्येक के पास फर्म के मुनाफे में क्रमशः 30%, 39%, 30% और 1% शेयर हैं। हम मूल्यांकन वर्ष 1947-48 के लिए निर्धारिती फर्म के मूल्यांकन से चिंतित हैं, जिसके लिए पिछला वर्ष 31 मार्च 1947 को समाप्त वित्तीय वर्ष था।

28 फरवरी, 1947 को, निर्धारिती फर्म ने अपने साझेदारों के माध्यम से गिलेंडर्स अर्बुथनॉट एंड कंपनी (जिसे अब आगे इस निर्णय में "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के पक्ष में उसके द्वारा रखे गए कुछ शेयरों और प्रतिभूतियों की "बिक्री के लिए समझौता" 75 लाख रूपये की राशि के लिए किया गया। दस्तावेज़ के अंतर्गत बेचे गए शेयरों और प्रतिभूतियों की गणना दस्तावेज़ के निचले भाग में की गई है। उस समझौते का खंड (2) प्रदान करता है:

> "चौदह लाख और नब्बे हजार रुपये की राशि पर विचार करते हुए, मौजूदा साझेदार कंपनी को पार्टनरशिप डीड (जिसका एक मसौदा मौजूदा साझेदारों और कंपनी द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है) के अधीन फर्म में

एक भागीदार के रूप में स्वीकार करेंगे। कंपनी की साख और मुनाफे में हिस्सेदारी निन्यानबे प्रतिशत है।"

एकमात्र अन्य खंड जो हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है वह खंड (3) है जिसमें लिखा है:

"इसके खंड 1 और 2 के अनुसार देय पचहत्तर लाख रुपये और चौदह लाख और नब्बे हजार रुपये की उक्त दो रकम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा और संतुष्ट किया जाएगा।

(ए) मौजूदा साझेदारों या उनके नामांकितों को आवंटन द्वारा चौंसठ लाख और नब्बे हजार रुपये की राशि के रूप में, चौसठ हजार नौ सौ रुपये के साधारण शेयरों में से प्रत्येक को पूरी तरह से एक सौ रूपये भुगतान के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए जमा किया जाता है।

(बी) मौजूदा साझेदारों या उनके नामितों को एक सौ रुपये के पच्चीस हजार प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयरों के आवंटन द्वारा पच्चीस लाख रुपये की राशि के संबंध में, सभी उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया। एक अन्य दस्तावेज़ जो उसी दिन अस्तित्व में आया। 28 फरवरी, 1947 साझेदारी विलेख है। उस दिन निर्धारिती फर्म का

पुनर्गठन हुआ और एक नई साझेदारी अस्तित्व में आई। नई साझेदारी में पाँच भागीदार शामिल थे। (1) "कंपनी"; (2) एसी ग्लैडस्टोन; (3) एसडी ग्लैडस्टोन (4) टीएस ग्लैडस्टोन और (5) ग्लेनडी लिमिटेड। इस नई साझेदारी में "कंपनी" का लाभ में 99 प्रतिशत हिस्सा था। शेष चार साझेदारों में से प्रत्येक के पास नई साझेदारी के लाभ में केवल एक/चौथाई प्रतिशत हिस्सेदारी थी।आगे विवेचन करने से पहले यह उल्लेख करना जरूरी है कि "कंपनी" पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। 1946 में "कंपनी" ने खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने और प्रीमियम पर अपने शेयर बेचने की अनुमति के लिए पूंजीगत मुद्दों के परीक्षक के पास आवेदन किया। मूल रूप से "कंपनी" का प्रस्ताव 100/- रुपये के अंकित मूल्य के अपने शेयरों को 145 रुपये से 175/- रुपये के प्रीमियम पर जनता को बेचने और रुपये के अंकित मूल्य के अपने तरजीही शेयर को बेचने का था। 1 से 5 रुपये के प्रीमियम पर 100/-। पूंजीगत मुद्दों के परीक्षक उस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। बाद में आगे के पत्राचार के बाद, पूंजीगत मुद्दों के परीक्षक ने "कंपनी" को खुद को एक सार्वजनिक कंपनी में

परिवर्तित करने की अनुमति दी और 100/- रुपये के अंकित मूल्य के अपने साधारण शेयरों को जनता को रुपये से अधिक के प्रीमियम पर पेश करें। 125/- प्रति शेयर और 25,000/- रुपये अंकित मूल्य के प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर। 100 प्रत्येक प्रीमियम पर रुपये से अधिक नहीं। 5/- प्रति शेयर।"

हमने पहले देखा है कि बड़ी संख्या में साधारण और साथ ही वरीयता शेयर निर्धारिती फर्म को उसके अंकित मूल्य पर हस्तांतरित किए गए थे।

निर्धारण वर्ष 1947-48 के लिए निर्धारिती फर्म का मूल मूल्यांकन 28 अगस्त, 1948 को कुल आय 12,90,829/- रुपये पर किया गया था। इसके बाद आयकर अधिकारी ने 2 मई, 1949 को धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही शुरू की और 16 जनवरी, 1956 को नया मूल्यांकन पूरा किया, जिसमें रुपये पर निर्धारित पूंजीगत लाभ का शुल्क लगाया गया। 1,03,16,786/-. निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की। इसने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विभिन्न दलीलें उठाईं। उन विवादों का जिक्र करना जरूरी नहीं है. हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए यह कहना पर्याप्त है कि इसने धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही शुरू करने की वैधता को चुनौती दी और आगे तर्क दिया कि कोई पूंजीगत लाभ

नहीं हुआ। दूसरी ओर उसने दावा किया कि उसे कुछ पूंजीगत हानि हुई है। अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही वैध रूप से शुरू नहीं की गई थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीगत लाभ हुआ था लेकिन उन्होंने इसकी गणना रुपये पर की। 70,9,124/-. निर्धारिती द्वारा आगे की अपील पर ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती द्वारा किया गया पूंजीगत लाभ केवल रु। 46,76,784/-. पहले उल्लिखित संदर्भ में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती द्वारा किया गया पूंजीगत लाभ रु। 27,04,772/-. पहले उल्लिखित संदर्भ में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती द्वारा किया गया पूंजीगत लाभ रु।

निर्णय के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या आयकर अधिकारी द्वारा धारा 34(1)(ए) की कार्यवाही वैध रूप से शुरू की गई थी। वह प्रावधान कहता है:

> "यदि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारिती की ओर से किसी भी वर्ष के लिए उसकी आय की रिटर्न धारा 22 के तहत करने में चूक या विफलता के कारण या उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करना है। उस वर्ष के लिए, आयकर के

दायरे में आने वाली आय, लाभ या लाभ उस वर्ष के मूल्यांकन से बच गए हैं या उनका कम मूल्यांकन किया गया है, या बहुत कम दर पर मूल्यांकन किया गया है, या अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बना दिया गया है, या अत्यधिक नुकसान हुआ है या मूल्यह्रास भत्ते की गणना की गई है... वर्तमान मामले में हमें बस यह देखना है कि क्या आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि निर्धारिती ने प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा नहीं किया था। अभिव्यक्ति का दायरा "निर्धारिती की ओर से विफलता... उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में की जांच इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में की गई है।"

इस विषय पर अग्रणी मामला है कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम। आयकर अधिकारी, कंपनी जिला, कलकत्ता इसमें इस न्यायालय ने बहुमत से माना कि चार साल की अवधि से परे, लेकिन आठ साल की अवधि के भीतर, संबंधित वर्ष के अंत से मूल्यांकन के संबंध में नोटिस जारी करने के लिए धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए,

दो शर्तों का पालन करना होगा संतुष्ट। पहला यह है कि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आयकर के दायरे में आने वाली आय, लाभ या लाभ का कम मूल्यांकन किया गया है; (1) यह है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा "अंडर-असेसमेंट" धारा 22 या (2) के तहत अपनी आय का रिटर्न देने में निर्धारिती की ओर से चूक या विफलता के कारण हुआ था। उस वर्ष के लिए अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में निर्धारिती की ओर से चूक या विफलता। ये दोनों शर्तें आयकर अधिकारी को चार साल की अवधि से अधिक लेकिन संबंधित वर्ष के अंत से आठ साल की अवधि के भीतर मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र मिलने से पहले संतुष्ट होने की पूर्व शर्त हैं। इस न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि धारा 34 में इस्तेमाल किए गए शब्द "उस वर्ष के लिए उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक या विफलता" प्रत्येक निर्धारिती पर उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करते हैं। मूल्यांकन के लिए कौन से तथ्य महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, यह हर मामले में अलग-अलग होता है। प्रत्येक मूल्यांकन कार्यवाही में, मूल्यांकन प्राधिकारी एक

निर्धारिती से देय उचित कर की गणना और निर्धारण के उद्देश्य से, उसे उन सभी तथ्यों को जानने की आवश्यकता है जो उसे सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। उसके पास मौजूद प्राथमिक तथ्यों से, चाहे निर्धारिती द्वारा खुलासा किया गया हो या उसके द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के आधार पर खोजा गया हो या अन्यथा, मूल्यांकन प्राधिकारी को कुछ अन्य तथ्यों के संबंध में निष्कर्ष निकालना होगा; और अंततः प्राथमिक तथ्यों और उनसे निकाले गए अतिरिक्त तथ्यों से, प्राधिकारी को उचित कानूनी निष्कर्ष निकालना होगा और कर अधिनियम की सही व्याख्या के आधार पर उचित कर लगाना होगा। जहां तक प्राथमिक तथ्यों का सवाल है, यह निर्धारिती का कर्तव्य है कि वह उन सभी का खुलासा करे- जिसमें खाता-बही में विशेष प्रविष्टियां, दस्तावेजों और दस्तावेजों के विशेष हिस्से और अन्य सबूत शामिल हैं जो दस्तावेजों से मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा खोजे जा सकते थे। और अन्य सबूतों का खुलासा किया गया। हालाँकि, कर्तव्य सभी प्राथमिक तथ्यों के पूर्ण और सच्चे प्रकटीकरण से आगे नहीं बढ़ता है। एक बार जब सभी प्राथमिक तथ्य मूल्यांकन प्राधिकारी के सामने आ जाते हैं, तो यह उसे तय करना होता है कि तथ्यों के कौन से निष्कर्ष उचित रूप से निकाले जा सकते हैं और अंततः कौन से कानूनी निष्कर्ष निकाले जाने हैं। यह किसी और के लिए नहीं था- करदाता के लिए तो दूर- मूल्यांकन प्राधिकारी को यह बताने के लिए कि तथ्यों या कानून के

बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि वास्तव में आयकर अधिकारी के लिए यह विश्वास करने के लिए कुछ उचित आधार हैं कि प्राथमिक तथ्यों के संबंध में कोई गैर-प्रकटीकरण हुआ है, जिसका अंडर-असेसमेंट के प्रश्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो अधिकार क्षेत्र देने के लिए पर्याप्त होगा। आयकर अधिकारी धारा 34 के तहत नोटिस जारी करेगा। क्या वे आधार इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे या नहीं कि भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था, यह अदालत की जांच के लिए खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में, अधिकार क्षेत्र देने के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि आयकर अधिकारी ने जब अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था तो उसके पास यह सोचने के लिए कुछ प्रथम दृष्टया आधार थे कि कुछ भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण हुआ है।

कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था आयकरआयुक्त, पश्चिम बंगाल, और अन्य बनाम। हेमचंद्र कर और अन्य,) इस न्यायालय द्वारा गुजरात आयकर आयुक्त बनाम भानजी लवजी के साथ-साथ आयकर आयुक्त कलकत्ता बनाम बर्लोप डीलर्स लिमिटेड में भी यही विचार व्यक्त किया गया था।

इन निर्णयों में निर्धारित नियम को ध्यान में रखते हुए अब हम इस मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें ताकि यह पता लगाया

जा सके कि क्या निर्धारिती प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए अपने मूल्यांकन के लिए सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में विफल रहा है। इस मामले में हम पूंजीगत लाभ से निपट रहे हैं। इसलिए जिन भौतिक तथ्यों का खुलासा किया जाना था वे पूंजीगत लाभ से संबंधित थे। हालांकि निर्धारिती के मूल मूल्यांकन के समय, पांच साझेदारों द्वारा दर्ज किया गया साझेदारी विलेख आयकर अधिकारी के समक्ष था, 28 फरवरी,1947 को "कंपनी"के पक्ष में निर्धारिती फर्म के साझेदारों द्वारा बिक्री विलेख उनके सामने रखा ही नहीं गया था. आयकर अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह यह निष्कर्ष निकाल सके कि निर्धारिती फर्म ने "कंपनी" को कोई शेयर और प्रतिभूतियां बेची थीं; न ही 1 जनवरी 1939 को उन शेयरों और प्रतिभूतियों के मूल्य के बारे में आयकर अधिकारी के सामने कोई सामग्री थी। इसके अलावा उनके सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि उन शेयरों और प्रतिभूतियों को "कंपनी" को बेच दिया गया था। 75 लाख रुपये की राशि. वास्तव में निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना रिटर्न पुराने फॉर्म में जमा किया था जिसमें पीटी शामिल नहीं था। VII जो पूंजीगत लाभ से आय के विवरण से संबंधित है। संलग्न विवरण में सद्भावना की बिक्री या "कंपनी" के शेयरों की बिक्री के लिए विचार के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल नहीं थे। यह बिना महत्व के नहीं है कि

निर्धारिती ने आयकर अधिकारी के समक्ष धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दी। अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष भी, एकमात्र बिंदु जो आग्रह किया गया प्रतीत होता है वह यह था कि चूंकि फर्म का पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठित फर्म को मूल्यांकन वर्ष 1947-48 में धारा 26-ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि मूल मूल्यांकन करते समय आयकर अधिकारी सभी भौतिक तथ्यों से अवगत थे। हम ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में विफल रहा है कि उसने कोई पूंजीगत लाभ कमाया है या नहीं।

अब हम इस प्रश्न पर जाते है कि क्या निर्धारिती ने प्रासंगिक लेखांकन वर्ष में कोई पूंजीगत लाभ कमाया था, यदि हां, तो उसके पूंजीगत लाभ की सीमा क्या है। पूंजीगत लाभ से संबंधित प्रावधान धारा 12-बी में पाया जाता है। अब हम उस प्रावधान के प्रासंगिक भाग को पढ़ेंगे।

> "धारा 12-बी(1). 31 मार्च, 1956 के बाद पूंजीगत संपत्ति की बिक्री, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ के संबंध में एक निर्धारिती द्वारा कर का भुगतान "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत किया

जाएगा, और ऐसे लाभ और लाभ को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें बिक्री, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण हुआ था।"

[उपधारा (1) के प्रावधान हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं]।

उप-1. धारा 12-बी का (2) कहता है:

"पूंजीगत लाभ की राशि की गणना उस विचार के पूर्ण मूल्य से निम्नलिखित कटौती करने के बाद की जाएगी जिसके लिए पूंजीगत संपत्ति की बिक्री, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण किया जाता है:

(i) केवल ऐसी बिक्री, विनिमय, त्याग या स्थानांतरण के संबंध में किया गया व्यय

(ii) पूंजीगत संपत्ति के निर्धारिती के लिए वास्तविक लागत, जिसमें पूंजीगत प्रकृति का कोई भी व्यय शामिल है और उसमें कोई भी वृद्धि या परिवर्तन करने में उसके द्वारा वहन किया गया है, लेकिन किसी भी व्यय को छोड़कर जिसके संबंध में कोई भी भत्ता किसी भी प्रावधान के तहत स्वीकार्य है। धारा 8, 9, 10 और 12;

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति निर्धारिती से पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करता है, चाहे बिक्री, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण द्वारा, वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ निर्धारिती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बिक्री, विनिमय, त्याग या स्थानांतरण इस धारा के तहत निर्धारिती के दायित्व से बचने या कम करने के उद्देश्य से किया गया था, उस विचार का पूरा मूल्य जिसके लिए बिक्री, विनिमय, त्याग या स्थानांतरण किया गया है, निरीक्षण सहायक की पूर्व मंजूरी के साथ किया जाएगा। आयकर आयुक्त को उस तिथि पर पूंजीगत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य माना जाएगा जिस दिन बिक्री, विनिमय, त्याग या हस्तांतरण हुआ था।

(धारा 12-बी का शेष भाग हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है)।"

आयकर अधिकारी की राय थी कि बेचे गए शेयरों और प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य रुपये से कहीं अधिक था। 75 लाख. माना कि 1 जनवरी, 1939 को उनकी मूल कीमत रु. 47,95,728/-. इसलिए उनके अनुसार, "कंपनी" ने उन शेयरों और प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य से कम पर

सुरक्षित किया। आयकर अधिकारी ने आगे देखा कि निर्धारिती फर्म के भागीदार "कंपनी" के एकमात्र भागीदार थे और आगे कहा कि बिक्री पूंजीगत लाभ कर की देयता को कम करने के उद्देश्य से कम कीमत पर की गई थी। आयकर अधिकारी की गणना के आधार पर, निवेश की बिक्री पर पूंजीगत लाभ रु. 75,86,960/-. सद्भावना के संबंध में आयकर अधिकारी ने 1 जनवरी, 1939 को वही मूल्य रु. 87,56,200/- और इसका 99 प्रतिशत हिस्सा रु. होगा। 86,67,648/-. निर्धारिती को सद्भावना के लिए रुपये की राशि प्राप्त हुई। 14,90,000/-. कंपनी ने साझेदारों की पूंजी की कमी का 99 प्रतिशत हिस्सा अपने ऊपर ले लिया। 19,98,849/- और इसका 99 प्रतिशत हिस्सा रु. 19,78,861/-. आयकर अधिकारी ने सद्भावना के 99 प्रतिशत का मूल्य रुपये आंका। 1,13,97,474/- रुपये का पूंजीगत लाभ शामिल है। 27,29,826/-. इस प्रकार आयकर अधिकारी के अनुसार शेयरों और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और सद्भावना के कारण कुल पूंजीगत लाभ रु। 1,3,16,786/-. जैसा कि पहले देखा गया था, इस राशि को अपीलीय सहायक आयुक्त और फिर ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी काफी हद तक कम कर दिया गया था।

निर्णय के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या धारा 12-बी का पहला प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित है। इस मामले में जिस बिक्री से हम चिंतित हैं, वह 28 फरवरी, 1947 को हुई थी। धारा 12-बी को

1 अप्रैल, 1947 से अधिनियम में शामिल किया गया था। बिक्री लेनदेन के समय ऐसा ही था, धारा 12-बी अधिनियम का हिस्सा नहीं था. इसलिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि "स्थानांतरण निर्धारिती की देनदारी से बचने या कम करने के उद्देश्य से किया गया था" -देखें आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम। जॉर्ज हेंडरसन एंड कंपनी लिमिटेड,. इसलिए निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के तथ्य उस धारा की उपधारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 12-बी(1) के दायरे में आते हैं।

हमने पहले देखा है कि कुल पूंजीगत लाभ की गणना में आयकर अधिकारी ने शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री के साथ-साथ सद्भावना के परिणामस्वरूप अर्जित पूंजीगत लाभ को ध्यान में रखा था। अपीलीय सहायक आयुक्त ने अपने आदेश में सद्भावना की बिक्री के परिणामस्वरूप अर्जित किसी भी पूंजीगत लाभ के बारे में कुछ भी विशेष नहीं कहा। ट्रिब्यूनल ने विभाग के इस मामले को खारिज कर दिया कि सद्भावना की बिक्री के परिणामस्वरूप कोई पूंजीगत लाभ हुआ था। इसने निर्धारिती के दावे को भी खारिज कर दिया कि सद्भावना की बिक्री के परिणामस्वरूप कुछ पूंजी हानि हुई थी। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत था। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को राजस्व या निर्धारिती द्वारा हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई

थी। इसलिए हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है. इसलिए विचार करने के लिए एकमात्र प्रश्न शेष है कि क्या निर्धारिती द्वारा कंपनी को शेयरों और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कोई पूंजीगत लाभ हुआ था। यदि हाँ तो वह राशि क्या है?

इस संबंध में पहला प्रश्न जो हमें तय करना है वह यह है कि क्या 28 फरवरी, 1947 के बिक्री समझौते के तहत किया गया लेनदेन बिक्री या विनिमय है या केवल एक पुन: समायोजन है। राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह वास्तव में एक विनिमय था, हालांकि रूप में यह एक बिक्री थी। निर्धारिती के अनुसार, यह महज पुनः समायोजन था। राजस्व ने अपीलीय सहायक आयुक्त या न्यायाधिकरण या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया कि उक्त लेनदेन बिक्री नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष यह पहली बार था कि यह तर्क दिया गया कि यह बिक्री नहीं थी। निर्धारिती का यह तर्क कि यह केवल पुनर्समायोजन था, अधिनियम के तहत अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी; यह तर्क खारिज कर दिया गया था।

राजस्व के साथ-साथ निर्धारिती के तर्क के प्रभाव को ठीक से समझा जाए तो यह है कि लेन-देन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने में, अदालत को लेन-देन के सार को ध्यान में रखना चाहिए, न कि किए गए समझौते के कानूनी प्रभाव को। एक प्रस्ताव जिसे कुछ निर्णयित मामलों से

कुछ समर्थन प्राप्त होता है। आयकर आयुक्त बनाम. कीकाभाई प्रेमचंद,, में इस न्यायालय ने कहा कि "यह अच्छी तरह से माना जाता है कि राजस्व मामलों में लेन-देन के केवल स्वरूप के बजाय उसके सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सर कीकाभाई प्रेमचंद के मामले (सुप्रा) में इसे कोर्ट की टिप्पणियों को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का आधार बनाया गया था। आयकर आयुक्त अतिरिक्त लाभ कर, बॉम्बे सिटी बनाम होमी मेहता, रोजर्स एंड कंपनी बनाम. आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी- II,., में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फर्म की संपत्ति का कंपनी को हस्तांतरण काफी हद तक और वास्तव में सदस्यों द्वारा किया गया एक पुनर्समायोजन था ताकि वे एक फर्म के बजाय एक कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय चला सकें और इसमें कोई मुनाफा नहीं हो। इससे व्यावसायिक अर्थ बने; इसलिए, कंपनी की संपत्ति का कंपनी को हस्तांतरण बिक्री नहीं थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कलकत्ता बनाम। मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी, यह न्यायालय में आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम। बीएम खरवार,, ने माना कि सर किकाभाई प्रेमचंद के मामले (सुप्रा) में इस आशय की टिप्पणियाँ कि राजस्व मामलों में लेनदेन के सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि इसके केवल स्वरूप को, इस सिद्धांत पर कोई संदेह पैदा करने के रूप में

नहीं पढ़ा जा सकता है कि वास्तविक कानूनी संबंध किसी लेन-देन से उत्पन्न होने वाली आय ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाली रसीद की करयोग्यता को निर्धारित करती है। प्रश्नगत अवलोकन को आकस्मिक माना गया और मामले के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं था। खार-वार के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने सर होमी मेहता के निष्पादकों के मामले (सुप्रा), रोजर्स एंड कंपनी के मामले (सुप्रा) और मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी के मामले (सुप्रा) में भी निर्णयों को अस्वीकार कर दिया। इसमें इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अब यह तय हो गया है कि कर लगाने वाले अधिकारी हकदार नहीं हैं, यह निर्धारित करने में कि क्या किसी रसीद पर कर लगाया जाना चाहिए, लेन-देन के कानूनी चरित्र को नजरअंदाज करना जो रसीद का स्रोत है और जिसे वे "मामले का सार" मानते हैं, उस पर आगे बढ़ना। कर लगाने वाला प्राधिकारी किसी लेन-देन के परिणामस्वरूप वास्तविक कानूनी संबंध निर्धारित करने का हकदार है और वास्तव में बाध्य है। यदि पार्टियों ने किसी युक्ति द्वारा कानूनी संबंध को छुपाने का विकल्प चुना है, तो कर लगाने वाले प्राधिकारी के पास इस युक्ति को उजागर करने और संबंध के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन लेन-देन के कानूनी प्रभाव को "लेन-देन के सार" की जांच करके विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनल ने माना है कि निर्धारिती फर्म और "कंपनी" के बीच दर्ज किया गया "बिक्री के लिए समझौता" एक वास्तविक लेनदेन है और वही बिक्री का सबूत है। यह मूलतः तथ्य की खोज है। उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष की पुष्टि की है। उस दृष्टि से, हम राजस्व के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विचाराधीन लेनदेन एक विनिमय था न कि बिक्री। हम समान रूप से निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह महज एक पुनर्समायोजन था।

विशिष्ट शर्तों में समझौते का खंड (1) कहता है कि "मौजूदा भागीदार बेचेगा और कंपनी पचहत्तर लाख रुपये की राशि के लिए शेयर और प्रतिभूतियां खरीदेगी।" उस समझौते का खंड (3) केवल बिक्री मूल्य की संतुष्टि का एक तरीका प्रदान करता है। बेचे गए शेयरों और प्रतिभूतियों के लिए पार्टियों द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य 75 लाख है और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है कि बिक्री मूल्य की संतुष्टि में कंपनी के शेयरों के आवंटन के कारण, निर्धारिती फर्म को कुछ लाभ मिले लेकिन यह बिक्री को विनिमय में परिवर्तित नहीं करता है।

आयकर आयुक्त, केरल बनाम। आरआर रामकृष्ण पिल्लई, में इस में न्यायालय ने विनिमय को बिक्री से अलग करते हुए कहा कि जहां व्यापार करने वाला व्यक्ति शेयरों के आवंटन के विचार से किसी कंपनी को संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो यह विनिमय का मामला होगा न कि बिक्री

का और लेनदेन की वास्तविक प्रकृति क्या होगी ? परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टांप शुल्क या अन्य कारणों से हस्तांतरित संपत्ति का मूल्य आवंटित शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर दिखाया गया है। दूसरी ओर व्यवसाय करने वाला कोई व्यक्ति अपने द्वारा शुरू की गई कंपनी से सहमत हो सकता है कि उसकी संपत्ति एक निश्चित धन प्रतिफल के लिए कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाएगी और दायित्व की संतुष्टि के लिए धन प्रतिफल के रूप में एक निश्चित चेहरे के शेयरों का भुगतान किया जाएगा। मूल्य अंतरणकर्ता को आवंटित किया जाएगा। ऐसे मामले में वास्तव में दो लेन-देन होते हैं, एक बिक्री का लेनदेन और दूसरा एक अनुबंध जिसके तहत कीमत चुकाने के दायित्व की संतुष्टि के लिए शेयर स्वीकार किए जाते हैं। तथ्य यह है कि "कंपनी" के शेयरों को निर्धारिती फर्म को हस्तांतरित करने के परिणामस्वरूप, बाद वाले ने काफी लाभ प्राप्त किया, लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को नहीं बदलेगा- इस न्यायालय के निर्णय को देखें चित्तूर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (पी.) लिमिटेड बनाम। आयकर अधिकारी, चित्तूर ,।

ऊपर बताए गए कारणों से, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि कंपनी और निर्धारिती के बीच "बिक्री के लिए समझौते" से प्रमाणित लेनदेन बिक्री था।

अब हम देखते हैं कि धारा 12-बी(2) का उस लेनदेन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस प्रावधान के तहत, पूंजीगत लाभ की राशि की गणना उस प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से कुछ कटौती करने के बाद की जानी है जिसके लिए बिक्री की गई है। "जिस प्रतिफल के लिए बिक्री की गई है उसका पूरा मूल्य" अभिव्यक्ति का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह वह प्रतिफल है जिसके भुगतान पर सहमति व्यक्त की गई है या यह उस प्रतिफल का बाजार मूल्य है? किसी मूल्य पर बिक्री के मामले में, विनिमय के मामले के विपरीत, किसी भी बाजार मूल्य का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए बिक्री के ऐसे मामलों में, जिनमें धारा 12-बी की उप-धारा (2) का पहला परंतुक लागू नहीं होता है, हमें बस यह देखना है कि किस कीमत पर सौदेबाजी की गई है। जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों के बारे में पहले बताया गया है, पहला प्रावधान लागू नहीं होता है। जैसा कि पहले देखा गया, शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए सौदेबाजी की गई कीमत केवल पचहत्तर लाख रुपये थी। इस मामले के तथ्य पूरी तरह से इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और अन्य में निर्धारित नियम के अंतर्गत आते हैं। बनाम जॉर्ज हेंडरसन एंड कंपनी लिमिटेड (सुप्रा)। उसमें इस न्यायालय ने कहा:

> "बिक्री के मामले में, प्रतिफल का पूरा मूल्य वास्तव में भुगतान किया गया पूरा बिक्री मूल्य है। विधायिका को

"प्रतिफल का पूर्ण मूल्य" शब्दों का उपयोग करना पड़ा क्योंकि यह न केवल बिक्री के साथ, बल्कि विनिमय जैसे अन्य प्रकार के हस्तांतरण से भी निपट रहा था, जहां प्रतिफल धन के अलावा अन्य होगा। यदि वर्तमान मामले में यह माना जाता है कि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमत 136 रुपये की दर से थी। 136 प्रति शेयर-प्रतिफल का पूरा मूल्य रुपये की दर से लिया जाना चाहिए। धारा 12 बी(2) के मुख्य भाग की व्याख्या के बारे में हमने जो विचार व्यक्त किया है, वह इस तथ्य से सामने आता है कि धारा 12(बी (2) के पहले परंतुक में, इस कल्पना को जन्म देने के लिए पहले परंतुक की दो शर्तें हैं (1) कि अंतरणकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरिती के साथ जुड़ा हुआ था, और (2) यह अंतरण दायित्व को टालने या कम करने के उद्देश्य से किया गया था। धारा 12 बी के तहत निर्धारिती। यदि इस परंतुक की शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो धारा 12 बी(2) का मुख्य भाग लागू होता है और आयकर अधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को ध्यान में रखना होगा।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस मामले में जो शेयर आवंटित किए गए थे उनका बाजार मूल्य रुपये था। 136/- प्रति शेयर था. 620/- प्रति शेयर।

उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए हम सोचते हैं कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य का पूरा मूल्य केवल पचहत्तर लाख रुपये था। ऐसा होने पर, कंपनी द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ रु। 27,4772/- जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठहराया।

परिणामस्वरूप ये दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और उन्हें जुर्माने सहित अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

के.बी.एन.

अपील समाप्त।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **राजेन्द्र बंशीवाल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।